

## नीतिआयोग की अभनिव भारत @75 कार्‍यनीति

### चर्चा मे?

नीतिआयोग ने 'अभनिव भारत @75 के लयि कार्‍यनीति' (Strategy for New India @ 75) जारी की है जसिमें 2022-23 हेतु उद्देश्यों को परभिषति कयिा गया है। यह 41 महत्त्वपूरण कषेत्रों का वसितृत वविरण है जसिमें पहले से हो चुकी प्रगतिको मान्यता दी गई है, प्रगतिके मार्ग में बाध्यकारी रुकावटों की पहचान की गई है और स्पष्ट रूप से वर्णति उद्देश्यों को प्राप्त करने के वषिय में सुझाव दयि गए है।

//

### चार खंडों में कयिा गया है वभिजन

- इस दस्तावेज़ के 41 अध्यायों को चार खंडों : वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस में वभिजति कयिा गया है।

### वाहक (Drivers)

- वाहकों पर आधारति पहला खंड आर्थकि नषिपादन के साधनों, वकिस और रोज़गार, कसिानों की आमदनी दोगुनी करने, वजिज्ञान प्रौद्योगकिी और नवोन्मेष पारसिथितिकिी को उन्नत बनाने और फनिटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते कषेत्रों को बढावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केंद्रति करता है।



वाहकों से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सफ़ारशों में शामिल हैं:

- वर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर प्राप्त करने के लिये अर्थव्यवस्था की गति को नरितर तेज़ी से बढ़ाना । इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में वसितार होगा और यह 2017-18 के 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी ।
- **सकल स्थायी पूंजी नरिमाण** (Gross Fixed Capital Formation- GFCF) द्वारा आँकी गई नविश दरों में GDP के मौजूदा 29 प्रतिशत में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36 प्रतिशत तक बढ़ाना ।
- कृषि क्षेत्र में, **ई-राष्ट्रीय कृषि भंडारियों (e-NAM) का वसितार** करते हुए तथा **कृषि उपज वपिणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी वपिणन अधिनियम** लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए ।
- **'शून्य बजट प्राकृतिक खेती'** की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना जिससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है । यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जाँची परखी पद्धति है ।
- रोज़गार के अधिकतम साधनों का सृजन सुनिश्चित करने के लिये श्रम कानूनों का संहिताकरण (codification) करने और प्रशिक्षुताओं को बढ़ाने के प्रबल प्रयास किये जाने चाहिए ।
- **खनन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति** का पुनर्नरिमाण करने के लिये **'एक्सप्लोर इन इंडिया'** (Explore in India) मिशन का आरंभ करना ।

### अवसंरचना (Infrastructure)

- दूसरा खंड अवसंरचना से संबंधित है जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है । यह भारतीय कारोबारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है ।

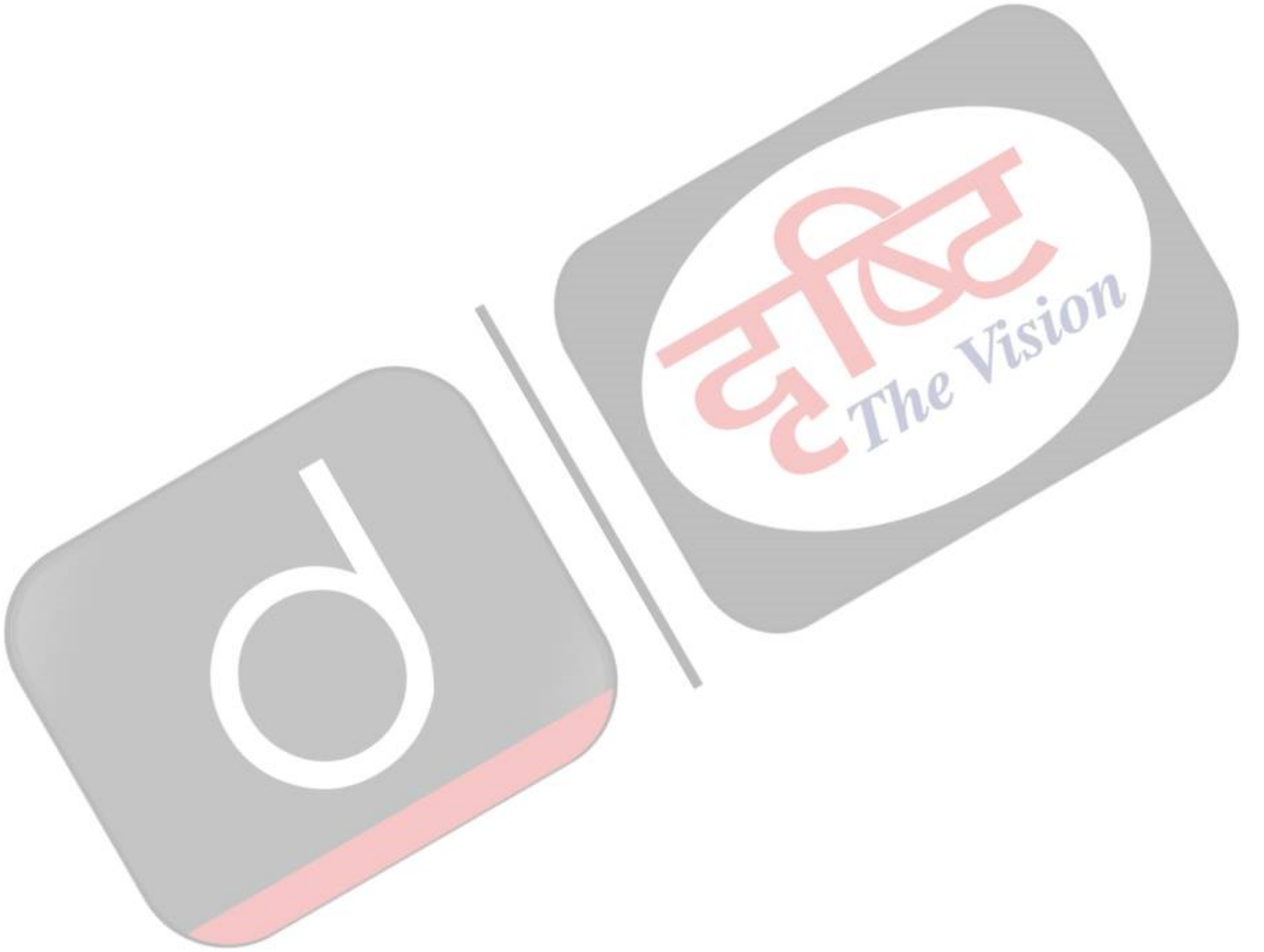


## अवसंरचना से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सफ़ािशों में शामिल हैं:

- पहले से मंजूर किये जा चुके रेल विकास प्राधकिरण (Rail Development Authority-RDA) की स्थापना में तेज़ी लाना । RDA रेलवे के लयि एकीकृत, पारदर्शी और गतशील मूल्य वयवस्था के संबंध में परामर्श देने या वविकपूरण नरिणय लेने का कार्य करेगा ।
- तटीय जहाजरानी और अंतरदेशीय जलमार्गों द्वारा फ़रेट परविहन के अंश का दोहरा करना । बुनयिदी ढाँचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरुआत में, वायबलिटी गैप फंडगि उपलब्ध कराई जाएगी ।
- परविहन के वभिन्न साधनों को एकीकृत करने तथा मल्टी-मॉडल और डजिटिइज़ड गतशीलता को बढ़ावा देने के लयि IT-सकषम मंच का वकिस ।
- 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डजिटिल रूप से जुड़ जाएंगी । वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएँ राज्य, ज़िला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

## समावेशन (Inclusion)

- समावेशन से संबंधित खंड समस्त भारतीय नागरिकों की कषमताओं में नविश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है । इस खंड के तीन वषिय स्वास्थ्य, शकिषा और परंपरागत रूप से हाशयि पर मौजूद आबादी के वर्गों को मुख्य धारा में लाने के आयामों के इर्द-गर्द घूमते हैं ।

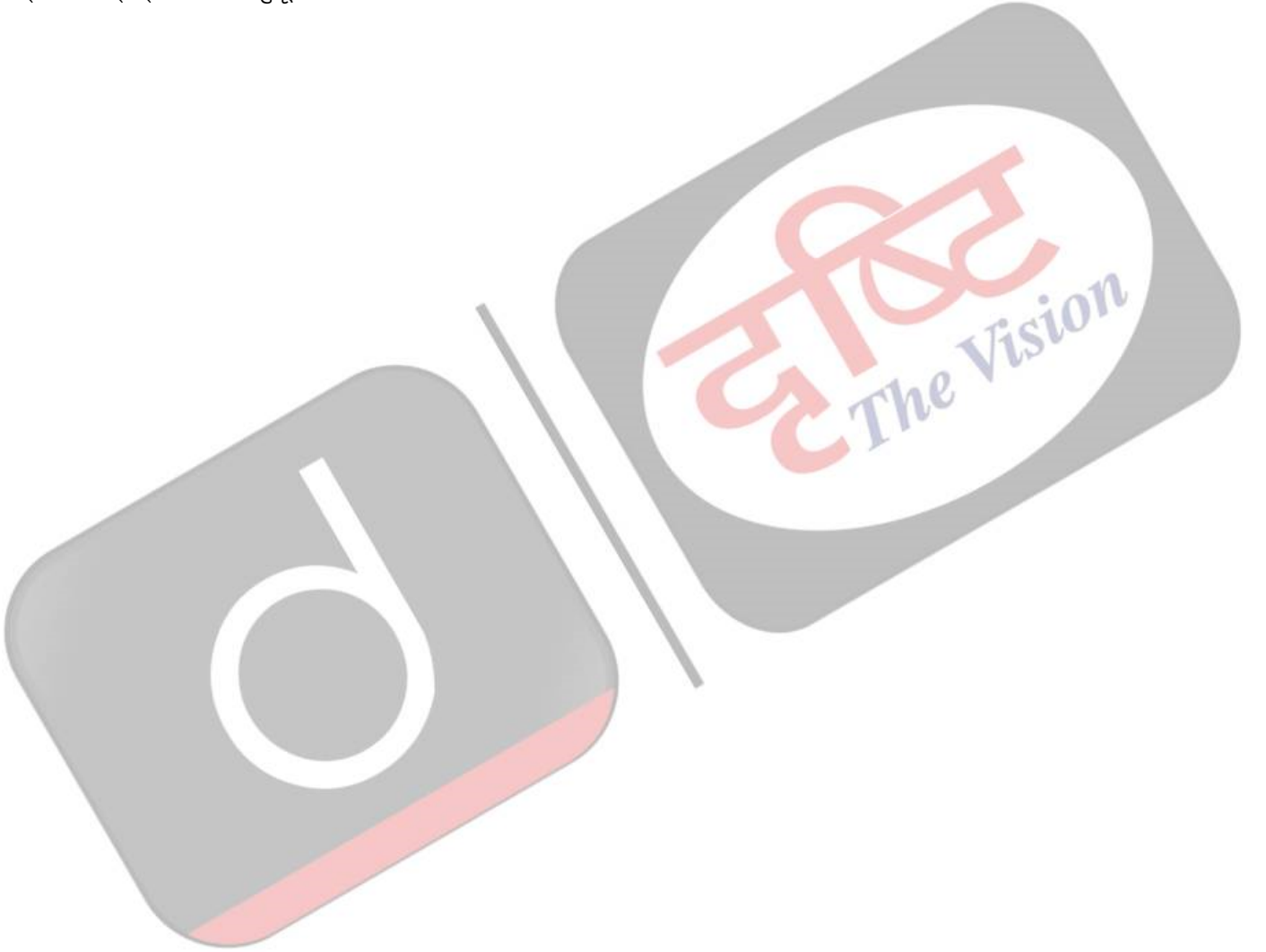


समावेशन से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सफारिशों में शामिल हैं:

- देश भर में 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (PM-JAY) प्रारंभ करने सहित आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन।
- केंद्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये फोकल प्वाइंट बनाना। समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
- 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टकिरगि लैब्स की स्थापना के ज़रिये जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के नषिकर्षों पर नजर रखने के लिये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्ररी की संकल्पना करना।
- आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह शहरी क्षेत्रों में भी कफायती घरों को प्रोत्साहन देना।

## गवर्नेंस (Governance)

गवर्नेंस से संबंधित अंतिम खंड में इस बात पर गहन चर्चा कियी गयी है कि विकास के बेहतर नषिकर्ष प्राप्त करने के लिये गवर्नेंस के ढाँचों को किस तरह सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है।

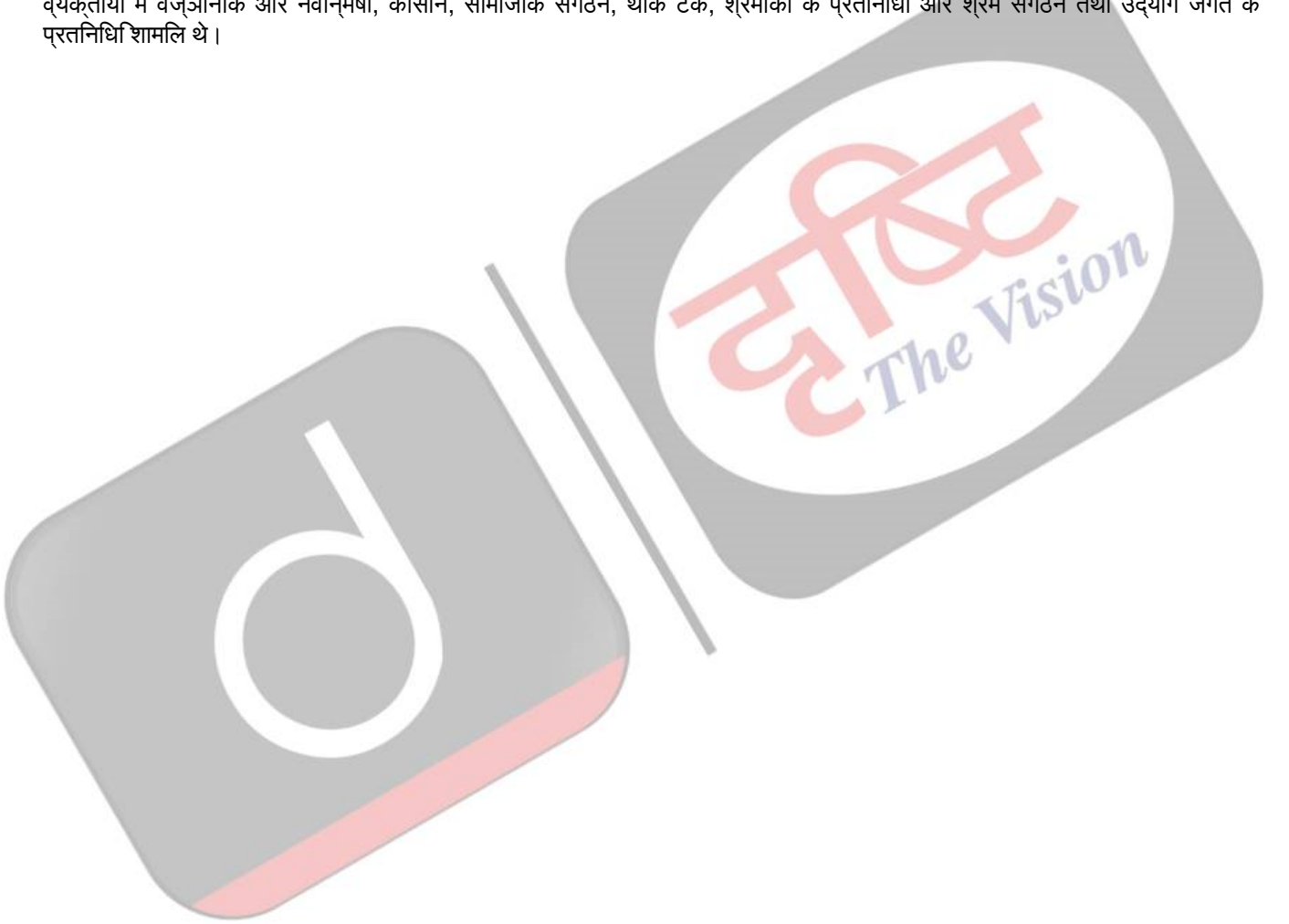


## गवर्नेस से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सफ़ारिशों में शामिल हैं:

- उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सफ़ारिशों (Second ARC Recommendations) जैसे- तरकसंगतता और सेवाओं में सामंजस्य के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग सविलि सेवाओं को कम करना, सविलि सेवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा को 2022-23 तक सामान्य श्रेणी के लिये 27 साल तक समिति किया जाना आदि का कार्यान्वयन करना।
- मध्यस्थता की प्रक्रिया को कफ़ायती और त्वरति बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिये मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायति मध्यस्थों का आकलन करने के लिये नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना।
- लंबति मामलों को नपिटाना- नयिमति न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरति करना।
- भराव के क्षेत्रों को कवर करने, प्लास्टिक अपशष्टि और नगर नगिम के अपशष्टि तथा अपशष्टि से धन सृजति करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मशिन के दायरे का वसितार करना।

## गहन वचिर-वमिरश के बाद बनी कारयनीति

- इस कारयनीतिको तैयार करने में नीतिआयोग ने अत्यंत सहभागतिपूरण दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। नीतिआयोग के प्रत्येक क्षेत्र में हतिधारकों के तीनों समूहों यथा कारोबारी व्यक्त, वैज्जानिकों सहति शकिषावदि और सरकारी अधिकारियों- के साथ गहन वचिर-वमिरश किया गया।
- इसके बाद, उपाध्यक्ष के स्तर पर हतिधारकों के 7 सेटों में से प्रमुख व्यक्तियों के वविधितापूरण समूह के साथ वचिर-वमिरश किया गया। इन प्रमुख व्यक्तियों में वैज्जानिक और नवोन्मेषी, कसिान, सामाजकि संगठन, थकि टैंक, शर्मकों के प्रतनिधि और शर्म संगठन तथा उद्योग जगत के प्रतनिधि शामिल थे।



- प्रत्येक अध्याय के मसौदे को वचिार-वमिर्श के लयि वतिरति कयिा गया और जानकारयिां, सुझाव तथा टपिपणयिां प्रापूत करने के लयि केंद्रीय मंत्रयिों को भी साथ जोड़ा गया । इसके दसूतावेज का मसौदा सभी राज्यों और संघ शासति प्रदेशों में भी वतिरति कयिा गया जहां से प्रापूत बहुमूल्य सुझावों को इसमें शामिल कयिा गया ।
- इस दसूतावेज को तैयार करते समय सरकार के भीतर- केंद्रीय राज्य और जलिा सूतर पर 800 के ज्यादा हतिधारकों और लगभग 550 बाहरी वशिषज्जों के साथ वचिार-वमिर्श कयिा गया ।
- इस कारयनीति दसूतावेज में नीतगित वातावरण में और सुधार लाने पर महत्त्वपूरण रूप से धयान केंदरति कयिा गया है, ताक निजी नविशक और अनूय हतिधारक अभनिव भारत 2022 के लयि नरिधारति लक्ष्यों की प्रापूत की दशिा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सके और 2030 तक भारत को 5 टरलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दशिा में आगे बढ़ा सके ।

इस दसूतावेज को शासन की पुनःकल्पना के संदरभ में तैयार कयिा जा रहा है । इसका कारण यह है क भारत को ऐसी 'Development State' में पहुँचने की जरूरत है जो प्रमुख वसूतुओं और सेवाओं के मुशकलि और उत्तरदायी वतिरण पर केंदरति हो । इसके लयि सार्वजनकि-नजी साझेदारी के इष्टतम सूतर को हासलि करने का सतत प्रयास कयिा जा रहा है । वसूतुओं और सेवाओं के अधिक कुशल वतिरण के लयि नीतयिां लागू की गई हैं जैसे-स्वास्थ्य, शकिषा, बजिली, शहरी जल आपूरति एवं संयोजकता (connectivity) । इस संदरभ में उदयमतिा और नजी नविश को बढ़ावा देकर लालफीताशाही और बोझलि वनियिमन को खतम करने के लयि एक सुचनितति प्रयास कयिा जा रहा है । साथ ही, 'अभनिव भारत @75 कारयनीतिां को संयुक्त राष्ट्र के SDG (Sustainable Development Goals) के साथ संरेखति करने का भी प्रयास कयिा जा रहा है, यही कारण है क कारयनीतिां के सभी अध्यायों को उक्त लक्ष्यों की प्रापूत के संदरभ में तैयार कयिा गया है । वर्तमान में भारत 'सबका साथ, सबका विकास' के दर्शन के साथ 'Development State' के रूप में परणित हो रहा है । 2022-23 में अभनिव इंडयिा के लक्ष्यों को प्रापूत करने के लयि सबसे महत्त्वपूरण यह है क निजी क्षेत्र, नागरकि समाज और यहाँ तक क सभी व्यक्तयिों को सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने और उनमें वृद्धि करने हेतु अपनी रणनीतिां तैयार करनी चाहयिे । इसमें कोई संदेह नहीं है क 21वीं शताब्दी में मौजूद प्रौद्योगिकी के साथ विकास की गति को व्यापक रूप दिया जा सकता है । सभी भारतीयों के संकल्प के साथ भारत को सदिधि प्रापूत होगी ।

सूतः : नीति आयोग, द हदि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/niti-aayog-releases-strategy-for-new-india>

